CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

आर्थिक सर्वेक्षण: भारत की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 427 ग्राम / दिन हुयी

पशुपालन जैसे कृषि संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने से वर्ष 2020-21 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता को 427 ग्राम प्रति दिन तक बढ़ाने में मदद मिली है, जो 2014-15 में 319 ग्राम थी। सोमवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से पता चला है कि 2014-15 से 2019-20 (स्थिर कीमतों पर) के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमान के अनुसार, 2014-15 में 24.32 प्रतिशत से बढ़कर कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 29.35 प्रतिशत (2019-20) का योगदान दे रहा है। 2019-20 में पशुधन क्षेत्र ने कुल जीवीए का 4.35 प्रतिशत योगदान दिया।

पशुधन उद्योग का कहना है कि बजट से झींगा और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा

"पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आरई 2021-22 में 8.86 बिलियन रुपये से बढ़ाकर 2022-23 बीई में 20.00 बिलियन रुपये, पशुधन बेहतरी का समर्थन करने पर भारत सरकार के फोकस को दोहराता है। इससे मवेशियों की उत्पादकता में वृद्धि होने और डेयरी प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए कच्चे दूध की उपलब्धता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दरों में कमी से डेयरी सहकारी समितियों के मार्जिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो डेयरी प्रसंस्करण में आगे CAPEX के लिए कुशन देंगे और डेयरी किसानों को लाभ देंगे, "अमित सरावगी, अध्यक्ष, पशुधन कार्यबल, CII पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने कहा।

हालांकि, पशुधन उद्योग के कप्तानों का मानना है कि बजट ने पशुधन क्षेत्र पर अपर्याप्त ध्यान दिया, भले ही यह सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का योगदान देता है।

गुजरात में जीसीएमएमएफ के दूसरे सबसे बड़े दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए रास्ता साफ हो गया है

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के राज्य के दूसरे सबसे बड़े दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सभी रास्ते साफ कर दिए गए हैं, जो राजकोट के पास बनेगा। यहां के जिला कलेक्टर ने शहर के बाहरी इलाके में भावनगर रोड पर 72 एकड़ जमीन चिन्हित की है। वर्तमान में, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के 12 जिलों से अतिरिक्त दूध जीसीएमएमएफ के गांधीनगर संयंत्र में भेजा जाता है। एक बार दूसरा संयंत्र तैयार हो जाने के बाद, जीसीएमएमएफ परिवहन लागत पर बचत करेगा।

भूमि की अनुमति मिलते ही जीसीएमएमएफ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहता है। नए राजकोट प्लांट में दुग्ध उत्पाद जैसे चॉकलेट, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, श्रीखंड का भी उत्पादन किया जाएगा।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का बजट आवंटन 44% बढ़ा

पेश किए गए वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,407.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट आवंटन में 44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा, “2022-23 में पशुधन के लिए बजट में 40% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 48% की वृद्धि की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पशुधन और डेयरी किसानों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चतुर्वेदी ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सहकारी समितियों के लिए कम वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार में कमी से भारत में हजारों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप देश के 8 करोड़ डेयरी किसानों की आय अधिक होगी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 2022-23 में बजट में 20% की वृद्धि से स्वदेशी गोजातीय आबादी की उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए निधि आवंटन में लगभग 60% की वृद्धि के साथ एक स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन से स्वस्थ पशुधन और स्वस्थ भारत सुनिश्चित होगा।

आंध्र सरकार और अमूल आंगनबाड़ियों तक दूध पहुंचाने को राजी

आंध्र प्रदेश सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर 'अमूल' कंपनी के जरिए आंध्र प्रदेश में तैयार दूध और बालामृतम (सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन फूड) को राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने आज मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शुक्रवार को कहा कि वे अनंतपुर जिले के 85 गांवों में एक और अच्छी पहल जगन्ना पलावेलुवा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रकाशम, वाईएसआर कडपा, चित्तूर, गुंटूर, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में पहले से ही लागू है और अनंतपुर में एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो जिले के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा, डेयरी किसानों को अतिरिक्त 5 से 20 रुपये का लाभ मिलता है।

उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि राज्य सरकार थोक दूध शीतलन सुविधाएं बना रही है और अमूल के परिणामस्वरूप, निजी फर्मों को अपना मूल्य बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। "हम दूध संग्रह घोटालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।"

मिल्मा ने दूध खरीद को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की

मिल्मा संबद्ध डेयरी सहकारी समितियों, जिनकी खरीद की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, को बढ़ावा देकर दक्षिणी जिलों में दूध संग्रह को बढ़ावा देना चाहती है। दक्षिणी क्षेत्र में चार जिलों में दैनिक दूध की खरीद में पिछले एक साल में 75,000 लीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी लगभग एक लाख लीटर की मांग-आपूर्ति का अंतर बना हुआ है, जो मिल्मा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (TRCMPU) को अगले दो वर्षों में पुल करने की उम्मीद है ।

TRCMPU, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा और अलाप्पुझा जिलों को शामिल किया गया है, ने उनारवु के लिए गुरुवार को पारित अपने वार्षिक बजट में 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो संबद्ध सहकारी समितियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई एक परियोजना है, जिसकी दैनिक दूध खरीद 200 लीटर से कम है।

मिल्मा ने फरवरी 2022 से शुरू होने वाले मालाबार क्षेत्र में डेयरी किसान वेतन बढ़ाने का भी फैसला किया है। शनिवार को, संघ की 32 वीं वार्षिक आम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि डेयरी किसानों को उनके दूध की गुणवत्ता के आधार पर अतिरिक्त 1 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया जाना चाहिए। मिल्मा मालाबार क्षेत्रीय संघ प्रमुख के.एस. मणि ने एक प्रेस बयान में कहा कि संघ ने इसके लिए 2.3 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

उत्तर-पूर्वी जिलों में पोषण सलाहकार केंद्र स्थापित करने के लिए ई-फीड स्टार्ट-अप की योजना

ई-फीड, उत्तर-पूर्वी जिलों में पोषण सलाहकार केंद्र स्थापित करने की एक स्टार्ट-अप योजना है जो स्थायी और जवाबदेह पशुपालन को बढ़ावा देगी। कंपनी के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में मवेशी, एक्वा, पोल्ट्री और पिगरीज में कुल 25,000 मीट्रिक टन फ़ीड की मांग है, जो कि फ़ीड उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अप्रयुक्त अवसर है। हाल के दिनों में, पूर्वोत्तर पशु चारा उद्योग के लिए एक पसंदीदा क्षेत्र के रूप में उभरा है।

असम में एक्वा, मत्स्य पालन, मवेशी और सुअर पालन के लिए उपयुक्त वातावरण और जलवायु है। स्थापित उद्योग खिलाड़ी और स्टार्ट-अप उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर सीमा के पास फीड प्लांट स्थापित करने में निवेश कर रहे हैं जो यूपी और पूर्वोत्तर दोनों की मांग को पूरा कर सकते हैं।

कई अध्ययनों के अनुसार, पशु पोषण पर ध्यान केंद्रित करने से कार्बन पदचिह्न और मीथेन सहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है। इस प्रकार, किसानों को बेहतर इनपुट प्रदान करना और सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए इसे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित बनाना कंपनी का मूल उद्देश्य है।

आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए मैसूर में गोशाला परियोजना शुरू की जाएगी

राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध के कारण आवारा गायों और अपने मवेशियों को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए मैसूर को जल्द ही अपनी पहली सरकारी गोशाला मिलेगी। यह गोशाला यहां से करीब 30 किमी दूर स्थित आयरहल्ली गांव में 10 एकड़ में प्रस्तावित है। विभिन्न कारणों से परित्यक्त गायों को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक गोशाला बनाने के सरकार के निर्णय के तहत इस गोशाला का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य में गोहत्या विरोधी अधिनियम लागू होने के बाद, किसान और डेयरी उद्योग में लगे लोग नर बछड़ों, जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया है और बैल जो पुराने हो गए हैं और खेती की गतिविधियों में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं को रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 500 गायों को समायोजित करने की क्षमता वाली परियोजना की अनुमानित लागत 1.84 करोड़ रुपये होगी।

डेयरी-टेक स्टार्ट-अप स्टेलप्प्स ने गायों के लिए एक कदम काउंटर बनाया है

बैंगलोर स्थित स्टेलप्प्स एक फार्म-टू-कंज्यूमर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से दूध की यात्रा पर दूध को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। स्टेलैप्स के सह-संस्थापक और सीईओ रंजीत मुकुंदन कहते हैं, "हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जो मवेशियों के लिए फिटबिट जैसा है। कंपनी का 'mooON' उपकरण जानवर के पैर के चारों ओर जाता है, और उनकी गतिविधि के स्तर को ट्रैक करता है।

मुकुंदन कहते हैं, जब गायें बीमार होती हैं, तो वे कम चलती हैं, और जब वे ओवुलेट कर रही होती हैं, तो वे अधिक चलती हैं। स्टेलैप्स स्टेप ट्रैकर्स की जानकारी को डेटा के साथ जोड़ती है जिसे किसान और पशु चिकित्सक स्मार्टफोन ऐप में दर्ज करते हैं, जो टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे नियमित प्रोटोकॉल के लिए रिमाइंडर जारी करता है। मुकुंदन कहते हैं कि स्वस्थ गायें अधिक दूध देती हैं, और अपने पशुओं को ट्रैक करके और बेहतर प्रबंधन करके, किसान पैदावार बढ़ा सकते हैं।

लेकिन स्टेलैप्स सिर्फ स्टेप काउंटर नहीं बना रहा है: 'mooON' डिवाइस दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उद्योग को स्मार्ट तकनीक से बदलने की एक बहुत बड़ी पहल का एक छोटा सा हिस्सा है।

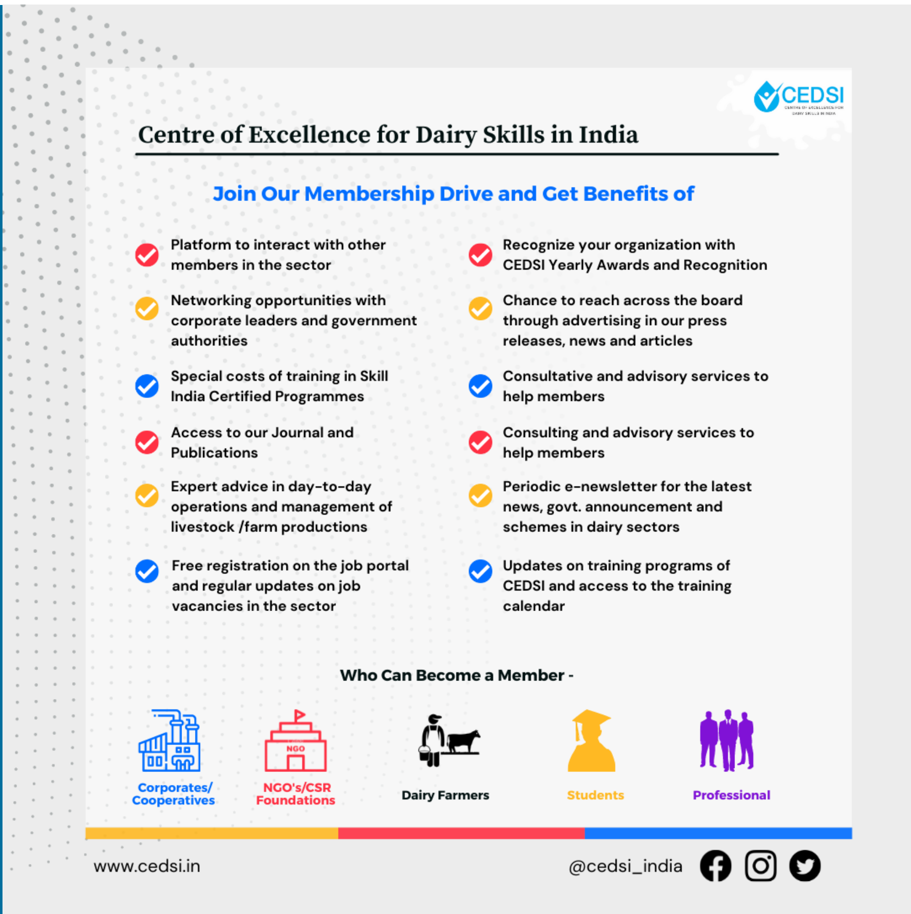

सीईडीएसआई ने डेयरी हितधारकों और व्यक्तियों से जुड़ने के लिए अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है और आपको/आपके संगठन को सीईडीएसआई का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। सीईडीएसआई के एक सदस्य के रूप में, आप/आपके संगठन को पूरे डोमेन में समान विचारधारा वाले व्यवसायों से जुड़ने का लाभ मिलेगा, व्यावसायिक अवसरों के लिए हमारे विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करें, सीईडीएसआई द्वारा प्रकाशित आंतरिक शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त करें, अपने कर्मचारियों के लिए हमारे स्किल इंडिया सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की विशेष लागत का आनंद लें, पूरे साल सीईडीएसआई द्वारा आयोजित वेबिनार और सेमिनारों तक पहुंच और कई अन्य लाभ।

अधिक जानकारी और सदस्य बनने के लिए हमें यहां लिखें: info@cedsi.in